

राज्य वधानसभा की बैठकें

प्रलिस के ललल:

राज्य वधानमंडल, संसद, अध्यादेश, गैर-सरकारी सदस्य वधलयक, संवधान के कामकाज की समीक्षा करने के ललल राष्ट्रीय आयोग

मेन्स के ललल:

सदन की बैठकों का महत्त्व, नषिकरयल बैठकों पर सुझाव, बैठकों में वृद्धलसे संबंधतल लाभ

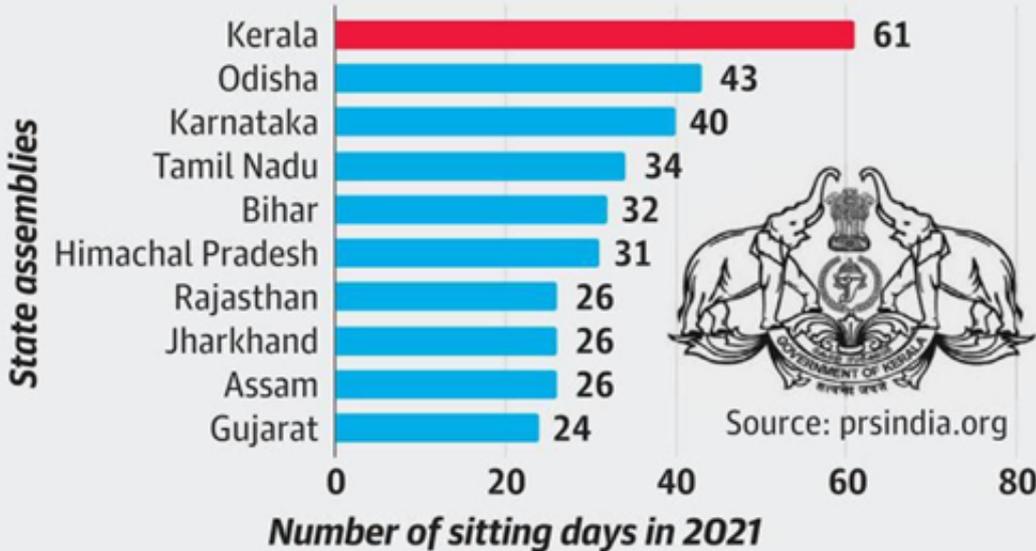
चर्चा में क्यों?

हाल ही में पीआरएस लेजसिलेटवल रसलरच द्वारा "राज्य कानूनों की वार्षकल समीक्षा, 2021" नामक शीर्षक से एक रषौरट जारी की गई थी ।

- रषौरट के अनुसार केरल को वर्ष 2021 में पहला स्थान प्राप्त हुआ, जसलमें इसकी वधानसभा की बैठक 61 दनलों तक चली, जो कसलसी भी राज्य में सबसे अधिक है ।
- [केरल में 144 अध्यादेश](#) भी जारी कयल गए, जो पछलले साल देश में सबसे अधिक थे ।

Counting the sittings

The chart shows the State Assemblies which sat for more than 20 sessions in 2021. Kerala recorded the most such sittings last year followed by Odisha and Karnataka



रषौरट के मुख्य बदुल:

■ बैठकें:

- मणपुर, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने प्रक्रिया नयियों के माध्यम से बैठक के दिनों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की है, जो पंजाब में 40 दिनों से लेकर उत्तर प्रदेश में 90 दिनों तक भिन्न-भिन्न है।
- वर्ष 2005 में कर्नाटक सरकार ने कम-से-कम 60 दिनों तक की बैठक की शर्त के साथ **कर्नाटक राज्य विधानमंडल में सरकारी कामकाज का संचालन अधिनियम** भी प्रस्तुत किया था।

■ अध्यादेश:

- इस मामले में केरल के बाद **20 अध्यादेशों के साथ आंध्र प्रदेश और 15 के साथ महाराष्ट्र** का स्थान रहा, जिनमें से 33 अध्यादेशों को प्रतिसिद्धि करने के लिये लाए गए विधायकों ने अधिनियम का रूप लिया।
- आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ने भी बजट प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिये अध्यादेश जारी किये।

■ विधायकों के पारित होने की स्थिति:

- 28 राज्य विधानसभाओं द्वारा अपनाए गए विधायकों में से 44% विधायकों को पेश किये जाने के एक दिन के भीतर ही पारित कर दिया गया।
 - गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब और बिहार उन आठ राज्यों में शामिल थे, जिनमें **पुरःस्थापन के दिन सभी विधायकों को पारित** किया।
- कर्नाटक, केरल, मेघालय, ओडिशा और राजस्थान ने अपने अधिकांश **विधायकों को पारित करने में पाँच दिन से अधिक का समय** लिया।
 - **केरल** में 94% विधायकों को विधायिका में पेश किये जाने के कम-से-कम पाँच दिनों के बाद पारित किया गया।
 - **मेघालय** के संबंध में यह दर 80% और **कर्नाटक** के मामले में 70% रही।

■ बैठकों के फोकस क्षेत्र:

- इस विषय से संबंधित वर्ष 2021 में पारित सभी कानूनों में से 21% के साथ **शिक्षा** सर्वोच्च प्राथमिकता थी।
- **शिक्षा**, कराधान और शहरी शासन के बाद वर्ष **2021 में पारित राज्य कानूनों का सबसे बड़ा हिस्सा** था।
- ऑनलाइन गेमिंग, राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों के लिये नौकरियों में आरक्षण तथा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित कई अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कानून शामिल हैं।

एक निष्क्रिय राज्यसभा:

■ संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिये राष्ट्रीय आयोग:

- संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिये राष्ट्रीय आयोग (2000-02), जिसकी अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम.एन. वैकटचलैया ने की थी:
 - विधायिका वाले राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के सदन:
 - 70 से कम सदस्यों (उदाहरण: पुदुचेरी) वाली विधायिका को वर्ष में कम-से-कम 50 दिन की बैठक करनी चाहिए।
 - अन्य राज्यों के सदन (जैसे-तमिलनाडु) के लिये वर्ष में कम-से-कम 90 दिन की बैठक करना अनिवार्य है।

■ पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन:

- जनवरी 2016 के दौरान गांधीनगर में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन ने सुझाव दिया:
 - राज्य विधानसभाओं में एक वर्ष में कम-से-कम 60 दिन की बैठक हो।
 - PRS के अनुसार, वर्ष 2016 और 2021 के बीच 23 राज्य विधानसभाओं में औसतन 25 दिनों की बैठक हुई थी।

सदन की बैठकों में वृद्धि से लाभ:

■ यथेष्ट/पर्याप्त चर्चा:

- सदनों (राज्य या संसद) में बैठक के दिनों में वृद्धि कर सदस्यों को विधायकों पर चर्चा के लिये अधिक समय मिला, साथ ही तथ्य और तर्क के आधार पर स्वस्थ बहस होगी जो अंततः सदन के स्वस्थ कामकाज को सुनिश्चित करेगी।

■ विधायकों को पारित करने में सुगमता:

- जैसे-जैसे सदन में बैठकों की संख्या बढ़ती है, किसी विशेष सत्र के दौरान सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले विधायकों की संख्या में वृद्धि होती है, इसके साथ ही पारित होने वाले विधायकों की संख्या में भी वृद्धि होती है।
 - विभिन्न क्षेत्रों में पारित विधायकों की संख्या में वृद्धि सरकार को **कुशल एवं प्रभावी शासन** लाने में सक्षम बनाएगी।

■ गलोटनि समापन:

- यह तब होता है जब समय की कमी के कारण एक विधायक (जिस पर चर्चा हो चुकी है) के साथ किसी अन्य विधायक या प्रस्ताव के ऐसे खंडों को भी मतदान के लिये रखा जाता है जिस पर चर्चा नहीं की गई है (क्योंकि चर्चा के लिये आवंटित समय समाप्त हो चुका होता है)।
 - बैठकों में वृद्धि से चर्चा के लिये अधिक समय मिला और **गलोटनि समापन** के मामलों में कमी आएगी।

■ नजी सदस्य विधायक:

- वर्ष 1952 के बाद से हजारों में से केवल 14 **नजी सदस्य विधायक** ही कानून बने।
 - बैठकों में वृद्धि से नजी सदस्यों को न केवल विधायक तैयार करने और सदन में पेश करने के लिये अधिक समय मिला, बल्कि इसके पारित होने हेतु वसित्तु एवं स्वस्थ चर्चा भी होगी।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs):

प्रारंभिक परीक्षा

प्रश्न. जब कोई वधियक संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भेजा जाता है, तो उसे किसके द्वारा पारति किया जाता है: (2015)

- (a) उपस्थति और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से
- (b) उपस्थति और मतदान करने वाले सदस्यों के तीन-चौथाई बहुमत से
- (c) सदनों के दो-तहाई बहुमत से
- (d) सदनों के पूरण बहुमत

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- भारतीय संवधान का अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधति है। संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा तब बुलाई जाती है जब एक सदन द्वारा पारति वधियक (साधारण) दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, या दोनों सदन अंततः वधियक में कयि जाने वाले संशोधनों पर असहमत होते हैं, या यदि 6 महीने से अधिकि समय बीत चुका है तो जसि सदन में पेश कयि गया है वह वधियक पर कोई कार्रवाई के बनिा पारति कर दिया हो।

मुख्य परीक्षा:

प्रश्न. भारतीय संवधान में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान है। उन अवसरों को गनाइये, जब सामान्यतः ऐसा होता है और उन अवसरों को भी जब ऐसा नहीं कयि जा सकता है, इसके कारण भी बताइये? (2017)

स्रोत: द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/state-assembly-sittings>

